जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 29 संख्याः 79 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार 21 जनवरी, 2022 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

अमेरिका के सैन डिएगो ज़ू में गंभीर रुप से संकटग्रस्त प्रजाति, सुमात्रन ओरांगुटान के एक बच्चे का जन्म हुआ है। जनवरी के आरंभ में 35 वर्षीय मादा ओरांगुटान, जिसका नाम इन्दाह है, ने एक संतान को जन्म दिया, जिसका नाम काजा रखा गया है। यह नाम इण्डोनेशिया के बोर्निओ के एक आईलैण्ड, कालीमंथन से प्रेरित है। सैनडिएगो में जन्मे ओरांगुटान का बोर्निओ के जंगलों में ही पुनर्वास किया जाता है। ज्ञातव्य है कि, सुमात्रन ओरांगुटान बेहद संकटग्रस्त प्रजाति है। असल में मादा ओरांगुटान तीन से पांच साल में एक बार एक बच्चे को जन्म देती है। इन्दाह ने भी इससे पहले 2014 में एक मादा को जन्म दिया था। सैनडिएगो ज़ू की अंतरिम एग्ज़ीक्युटिव डायरैक्टर, एरिका कोलर ने कहा कि ''गंभीर रुप से संकटग्रस्त इस प्रजाति के बच्चे के जन्म से भविष्य के लिए उम्मीद जगी है। काजा स्वस्थ हैं, उसकी मां को अवश्य प्रसव के बाद कुछ समस्या हो गई हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ, मां और बच्चे की पूरी निगरानी कर रहे हैं।'' लाल रंग के फर वाले ये ओरांगुटान अपना पूरा जीवन पेड़ों पर गुजार देते हैं। असल में इनके नाम, ''ओरांगुटान'' का मलय भाषा में अर्थ है जंगल का मानव। ओरांगुटान की कुल तीन प्रजातियां हैं। सुमात्रन, बोर्निअन और तापानुली। ये सभी बोर्निओ व सुमात्रा के वर्षावनों में रहती हैं। तापानुली को तो 2017 में ही अलग प्रजाति के रुप में मान्यता मिली है। इन्टरनैशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर की रैड लिस्ट में तीनों प्रजातियां गंभीर रुप से संकटग्रस्त बताई गई हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार एक सदी पहले तक 2.30 लाख ओरांगुटान थे लेकिन अब सुमात्रन ओरांगुटान की आबादी 14,000, बोर्निअन ओरांगुटान की आबादी लगभग एक लाख और तापानुली ओरांगुटान की आबादी 800 रह गई है। तीनों प्रजातियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इसका मुख्य कारण प्राकृतिक आवास का विनाश जंगल की कटाई और पामऑइल प्लान्टेशन तथा सड़क निर्माण आदि है। कई बार तो स्थानीय लोग भोजन के लिए भी इनकी हत्या कर देते हैं।

यू.पी. चुनाव ''बैकवर्ड व फॉरवर्ड'' के संघर्ष में तब्दील होगा?

योगी आदित्यनाथ (राजपूत) गोरखपुर से व अखिलेश यादव (बैकवर्ड) के करहल (मैनपुरी) से चुनाव लड़ने की घोषणा से यू.पी. का चुनाव फॉरवर्ड-बैकवर्ड के संघर्ष में परिवर्तित होना ही था

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अध्यक्षीय चुनाव के रूप में उभरकर आ रहा है। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह निर्णय ले लिया है कि वे मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट से खड़ा कर दिया है तथा यहां से सपा के प्रत्याशी की घोषणा चंद रोज़ में ही संभावित है- इस प्रकार उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई ''व्यक्तित्वों के टकराव'' (पर्सनलिटी क्लैश) के ईद-गिर्द केन्द्रित होती प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की लड़ाई, चुनाव-प्रचार को ''पिछड़े बनाम अगड़े'' की लड़ाई का रूप देने का अवसर यादव को उपलब्ध करा रही है। लेकिन चुनाव लड़ने को निर्णय लेना तथा विधान परिषद के माध्यम से विधायक बनने का विकल्प नहीं चुनने के सपा प्रमुख के लिए नुकसान भी हैं।

योगी आदित्यनाथ पिछले 28 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के पहले प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल में वे भी विधान परिषद के सदस्य रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने पूर्ववर्ती कार्यकालों में मायावती और यादव रहे थे। इसलिये प्रश्न यह है: क्या अखिलेश चुनाव लड़ने के दबाव के आगे झुककर भाजपा की चाल का शिकार हो गये हैं?

- **28 साल बाद कोई मु.मंत्री चुनाव लड़ने उतरा है यू.पी. में। अब तक मु.मंत्री, चाहे मायावती हों या अखिलेश यादव, विधान परिषद का सदस्य बनने का आसान रास्ता अपनाते आये हैं।**
- **अखिलेश के चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि, अखिलेश भाजपा के ''ट्रैप'' में फंस गये, क्योंकि वे अब अपने चुनाव क्षेत्र में बंधकर रह जायेंगे तथा पूरे राज्य में प्रचार के लिये उपलब्ध नहीं हो पायेंगे।**
- **पर अखिलेश समर्थक कह रहे हैं कि, अपनी सीट पर बंध जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के आदेशों के अंतर्गत रैली, जुलूस व आमसभाएं तो वैसे भी आयोजित नहीं की जा सकतीं।**
- **इन समर्थकों के अनुसार, अखिलेश के चुनाव लड़ने से सपा को लाभ ही मिलेगा, क्योंकि ''फ्लोटिंग वोट'' अब सपा की ओर झुकेंगे।**

यादव ने पहले तो स्वयं के चुनाव लड़ने की संभावना सिरे से खारिज कर दी थी, हाँ, उन्होंने अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करते हुये कहा कि ''अगर पार्टी ने चाहा तो वे चुनाव लड़ेंगे। सपा सूत्रों ने कहा कि अखिलेश ने अतिरिक्त या वैकल्पिक उपाय के रूप में दो विधानसभा क्षेत्र चिन्हित किये थे- आज़मगढ़ जिले की गोपालपुर सीट तथा बदायूँ जिले की गुन्नौर सीट। लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, सपा अध्यक्ष का झुकाव करहल सीट से चुनाव लड़ने की तरफ ज्यादा है, जो 2007 के अलावा, 1993 से लेकर अब तक सपा के पास ही रही है। 2007 में, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी, जो बाद में सपा में शामिल हो गया था।

चुनाव लड़ने या न लड़ने के यादव के निर्णय से सपा की संभावनाओं पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन सपा के नेतागण फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि अखिलेश के चुनाव लड़ने से वास्तव में मदद मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के परिदृश्य में किधर भी मुड़ जाने वाले मतदाताओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विदेशी पक्षी कुरजां के 10 से ज्यादा शव मिले

जैसलमेर, 20 जनवरी (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के लाठी इलाके में विदेशी पक्षी कुरजां के 10 से ज्यादा शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वन्यजीव प्रेमियों ने लाठी इलाके के डेलासर गांव के निकट कोजेरी नाडी के पास कुरजां बिखरे शवों को देखा है। उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। वन्य जीव प्रेमियों ने पक्षियों में बर्ड फ्लू या फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। अब वन विभाग की जांच के बाद ही विदेशी पक्षियों की मौत की वजह का खुलासा होगा।

- **इन मौतों का कारण बर्ड फ्लू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।**

वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पेमानी ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वो डेलासर गांव के पास घूमने निकले तब कोजेरी नाडी के आसपास के इलाके में कुरजां पक्षियों के 10 से अधिक शव पड़े मिले। एक साथ इतने पक्षियों के शव देखकर वे चौंक गए। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। पेमानी ने बताया कि संभवतया इनकी मौत खेत में यूरिया आदि खाने से हुई होगी । अगर ऐसा नहीं है तो फिर बर्ड फ्लू से भी मौत हो सकती है। जैसलमेर के वन्य जीव इलाकों में इन दिनों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'2024 से पहले, दिल्ली को जोड़ने वाले, सभी सड़कों के प्रोजैक्ट पूरे करें'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई.) को निर्देश दिये हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े सभी राजमार्गों को 2024 के आम चुनावों से पहले निर्धारित समय से पूर्व ही पूरा कर दे ताकि चुनावों के समय इस काम को मोदी सरकार की उपलब्धि एवं सफलता के रूप में जनता के सामने रखा जा सके।

8 लेन का ग्रीन फील्ड दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे मार्च 2024 में पूरा होना था लेकिन एन.एच.ए.आई. ने मंत्री को आश्वस्त कर दिया है कि यह दिसमबर 2023 तक पूरा हो जायेगा। हो सकता है कि नॉएडा के नजदीक स्थित न्यू जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस वे के हिस्से को पूरा होने में मार्च 2024 तक का समय लग जाये। एन.एच.ए.आई. एक्सप्रेस वे को समय पर पूरा कर देने का विश्वास जताया है। इसके अधिकारियों का कहना है कि गुड़गाँव से जुड़ने वाला इस एक्सप्रेस वे का 156 किमी लम्बा भाग इस वर्ष जून तक ट्रैफिक के लिये खुल जायेगा।

- **सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 के चुनाव तक सरकार के प्रति माहौल चमकाने के लिये, अपने विभाग को आदेश दिये।**

दिल्ली और हरियाणा के बीच 8 लेन का द्वारका एक्सप्रेस वे इस वर्ष ही जनता के लिये खुल जायेगा, जबकि इसके पूरे होने की मूल अंतिम तिथि अगस्त 2023 थी। इस एक्सप्रेस वे का 19 किमी का हिस्सा अगस्त तक तथा शेष 10 किमी हिस्सा दिसम्बर तक खुल जायेगा, जिसके बाद सड़क के इस हिस्से में ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो जायेगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे की पूर्णता की अंतिम तिथि भी जनवरी 2024 से बदलकर नवम्बर 2023 कर दी गई है। वस्तुतः, 210 किमी लम्बा यह एक्सप्रेस वे मार्च 2023 तक पूरा हो जाता, लेकिन देहरादून के निवासियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिकाओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। शीर्ष अदालत ने अब इस एक्सप्रेस वे को चौड़ा करने की स्वीकृति दे दी है जिससे कि चीन सीमा तक हमारे सैन्य वाहनों के पहुँच सकने की जरूरत पूरी हो सके।

सीसीटीवी में दिखी बस के साथ घटना स्थल पहुंची पुलिस

अलवर, 20 जनवरी (निसं)। पुलिस ने लहूलुहान मिली मूकबधिर नाबालिग बालिका की गुत्थी सुलझाने के लिए बुधवार आधी रात को पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस नाबालिग की जगह डमी लेकर गई। लोक परिवहन बस वही थी, जो 11 जनवरी को पुलिया पर सवारी उतारने रुकी थी। सीन रिक्रिएट करने के बाद निकले नतीजों का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है।

- **अलवर पुलिस ने आधी रात को मौके पर सीन रीक्रिएट किया। हालांकि बस चालक का कहना है कि, उसने ना तो किसी लड़की को देखा ना ही एक्सीडेंट।**

उधर, बस ड्राइवर का कहना था कि वह पूरे घटनाक्रम से अंजान है। ड्राइवर के अनुसार उसने न तो नाबालिग को देखा और न ही एक्सीडेंट। हां, पुलिया के ऊपर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिटेन लगभग सभी कोविड प्रतिबंध हटायेगा

उदाहरण के लिये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूलों व कक्षाओं में मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त होगी। कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इंग्लैंड में कोविड संबंधी लगभग सभी शेष प्रतिबंध अगले सप्ताह से समाप्त होने शुरु हो जायेंगे, क्योंकि उन पर आरोप लगाये थे कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ''डाउनिंग स्ट्रीट'' में पार्टियों के विषय में झूठ बोला था, उन आरोपों को लेकर अपेक्षित समर्थ-सहयोग के जबरदस्त अभाव को समाप्त करने के लिये संघर्षरत हैं।

''न्यूयॉर्क टाइम्स'' के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि जॉनसन की बुधवार की यह घोषणा उन करीब 100 कन्ज़र्वेटिव जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में लाने की एक कोशिश है, जो उस समय उनके खिलाफ हो गये थे, जब उन्होंने पिछले महीने कोविड नियंत्रण के लिये विभिन्न कदम उठाये थे। ''डाउनिंग स्ट्रीट'' पार्टियों के विषय में हुये अनेक रहस्योद्घाटनों के कारण उन सांसदों में यह साहस पैदा हो गया कि वे जॉनसन सरकार को गिराने के लिय अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये जोर लगायें।

- **न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि, यह प्र.मंत्री बोरिस जॉनसन का, उन 100 कंज़र्वेटिव सांसदों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास है, जो उनके विरोध में आ गये थे, जब उन्होंने ये प्रतिबंध लगाये थे।**
- **जैसा कि विदित ही है, बोरिस जॉनसन पर त्याग पत्र देने का भारी दबाव था, जब से यह खबर लीक हुई थी कि, कोविड के दौरान उनके ऑफिशियल निवास, 10, डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टियों का दौर चलता था।**

कोविड-नीति में परिवर्तनों का अर्थ होगा कि सार्वजनिक आवागमन तथा स्कूल-कक्षाओं में फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा, कर्मचारियों को दफ्तर आने के लिये प्रेरित-प्रोत्साहित किया जायेगा तथा बड़े समारोह-स्थलों में प्रवेश के लिये वैक्सीन प्रमाण-पत्र या हाल ही हुये

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमण

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। शीर्ष अदालत के कई जजों के कोविड-19 की नई लहर में संक्रमित हो जाने से सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना को कोर्ट में देर शाम तक रूककर यह

- **सुप्रीम कोर्ट के एक दर्जन जज करोना संक्रमित हो गए हैं, जिससे कोर्ट का दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।**

तय करना पड़ रहा है कि विभिन्न बैंचों की अध्यक्षता के लिए अगले दिन कौन-कौन से जज मौजूद रह सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में कई बैंचों में तीन जज है लेकिन सी.जे.आई. अब मजबूरी में दो जजों की बैंचे ही गठित कर रहे हैं।

वरिष्ठ वकील सी.ए. सुंदरम द्वारा सटर्लाइट इण्डस्ट्री के मामले की सुनवाई शीघ्र किए जाने की इच्छा जताने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक के बाद एक सर्वे, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन को ''फेलियर'' बता रहा है

15 व 16 जनवरी के बीच किये गये नवीनतम सर्वे के अनुसार, 37 प्रतिशत जनता बाइडन को असफल (फेलियर) मानती है, राष्ट्रपति के रूप में

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। अमेरिका के लोगों का मूड यह बयां करता है कि जनवरी 2021 में डैमोक्रेट्स के सत्ता में आने का जश्न अब लगभग समाप्त हो गया है।

एक के बाद एक सर्वेक्षणों में मिली हार बाइडन के सामने है, क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया है। सी.बी.ए. न्यूज/यू.जी.ओ.वी. सर्वे के एक दिन बाद आया पॉलिटिको/मॉर्निंग कन्सल्ट का नवीनतम सर्वेक्षण कार्य प्रदर्शन को लेकर बाइडन को ''विफल'' ग्रेड देता है।

37 प्रतिशत प्रतिभागियों ने उन्हें ''विफल'' अंक दिए, जबकि 12 प्रतिशत ने ''डी'' और 18 प्रतिशत ने ''सी'' ग्रेड दी और 20 प्रतिशत ने कहा कि वे ''बी'' ग्रेड के योग्य हैं। सिर्फ 11 प्रतिशत वोटर्स ने कहा कि जो ने ''ए'' ग्रेड अथवा ''उत्कृष्ट'' अंक दिए जाने योग्य कार्य किया है।

- **इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत जनता उनके कामकाज को ''डी'' ग्रेड स्तर का मानती है। 18 प्रतिशत उन्हें ''सी'' ग्रेड (एवरेज) स्तर का राष्ट्रपति आंकती है। केवल 20 प्रतिशत जनता उन्हें ''बी'' ग्रेड देने को राजी है तथा केवल 11 प्रतिशत जनता उनके कामकाज को ''उत्तम'' (एक्सलैंट) आंकती है।**
- **अधिकतर जनता राष्ट्रपति बाइडन को विदेशी राष्ट्रों से संबंधों के मामलों में, कोविड-19 से निपटने में तथा इकॉनमी को स्वस्थ रखने में असफल मानती है।**
- **और अधिक दुखद समाचार यह है कि, सर्वे के अनुसार 41 प्रतिशत जनता मानती है कि, समय के साथ बाइडन का कामकाज और गिरता जायेगा।**
- **बाइडन के साथ-साथ उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को भी असफल मानती है जनता।**

विदेशी मामलों, कोविड-19 और अर्थव्यवस्था को लेकर करीब आधे वोटर्स ने भी बाइडन को एक विफल ग्रेड दी।

पॉलिटिको एण्ड मॉर्निंग कन्सल्ट ने 15 से 16 जनवरी के बीच 2005 रजिस्टर्ड वोटर्स का सर्वे किया था।

न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले वर्ष के जनवरी माह में जब राष्ट्रपति बाइडन ने पदभार ग्रहण किया था, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 50 से भी अधिक थी, लेकिन अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी की गलती करोना वायरस की ओमक्रॉन लहर और बढ़ती महंगाई सहित पिछले छह माह में हुए शृंखलाबद्ध संकटों के बाद उनकी रेटिंग गिरकर 41 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर बाइडन को न्यूनतम अंक मिले। प्रतिभागियों के 52 प्रतिशत ने उन्हें इस मामले में एक विफल ग्रेड दी। यह निष्कर्ष अमेरिकी संसद कैपिटॉल हिल में हुए उपद्रवों की पहली बरसी के बिल्कुल बाद सामना आए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मूल निवास

जोधपुर, 20 जनवरी (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरूवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि शादी होने के आधार पर किसी महिला का मूल निवास स्थान नहीं बदला जा सकता। वह अपने माता-पिता के रहने के स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की हकदार है। टीएसपी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन खारिज किए जाने के बाद एक महिला ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

- **शादी होने पर भी महिला का मूल निवास नहीं बदला जा सकता, हाई कोर्ट ने निर्णय लिया।**

बड़ी सादड़ी निवासी 26 वर्षीय अनिता सुथार ने याचिका दायर कर कहा था कि उसका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ। बरसों तक वह अपने माता-पिता के साथ वहां रही। उसके पास चित्तौड़गढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र भी है। शादी के बाद वह अपने ससुराल बड़ी सादड़ी आ गई। चित्तौड़गढ़ टीएसपी क्षेत्र में आता है। ऐसे में उसने तहसीलदार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)